सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 10 ● अंक: 175 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, मंगलवार, 30 जुलाई, 2024
मूल्य ₹ 3/-

सफलता की खुशी मनाना अच्छा है पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना।

-बिल गेट्स

मनु-सरबजोत ने साधा ऐतिहासिक... 7 | सियासत के नए-नए रंग, बढ़ा... 3 | केशव केवल बड़बोले, उनके पास... 2

एक और रेल हादसा, विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेरा

» विपक्ष का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर हमला, नेता बोले- रेल नहीं रील मंत्री हैं

» शिवसेना यूबीटी, टीएमसी व सपा ने उठाए सवाल

» झारखंड में पटरी से उतर गए 18 डिब्बे

2 लोगों की मौत और 20 अन्य लोग घायल

ट्रेन दुर्घटना का रिकॉर्ड बनाने जा रही सरकार : अखिलेश

झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लगता ये है कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था लगता है उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उनके पास इतना बड़ा बजट है फिर भी दुर्घटना क्यों हो रही हैं? लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। आज की घटना में जिन लोगों की जान गई उनके लिए सरकार कुछ करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उस के लिए कोई पुख्ता इंतजाम करें।

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में मंगलवार तड़के मुंबई-हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण दो लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए। महीने भर के अंदर घटे चौथे रेल हादसे को लेकर विपक्ष के निशाने पर भी एनडीए सरकार आ गई है। सपा, कांग्रेस, टीएमसी से लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने रेल मंत्री पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें रील मंत्री बता दिया।

उधर अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि यह दुर्घटना तड़के पौने चार बजे दक्षिण-पूर्व रेलवे (एसईआर) के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ाबम्बू के पास हुई। एसईआर के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने बताया कि पास में एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये दोनों दुर्घटनाएं एक साथ हुई हैं।

शर्मनाक है उदासीनता, अब तक जवाबदेही नहीं : प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रेल संबंधी दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया और उस पर शर्मनाक उदासीनता का आरोप लगाया। चतुर्वेदी ने कहा, कई मौतों और आज तक कोई जवाबदेही नहीं होने के कारण, मुझे लगता है कि इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुआवजे की घोषणा करें, जांच का वादा करें और दूसरे पीआर इंस्टाग्राम रील पर आगे बढ़ें। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर हमला करते हुए उन्हें रील मिनिस्टर कहा और ट्रेनों में भीड़भाड़ की आलोचना करते हुए कहा, लोग शौचालयों में यात्रा कर रहे हैं लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती।

हर हफ्ते हो रहीं ये घटनाएं, क्या यही है शासन : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है। झारखंड में हुए रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आखिर भारत सरकार की संवेदनहीनता का अंत कब होगा? ममता बनर्जी ने पोस्ट किया कि ट्रेन हादसे अब नियमित से हो गए हैं। हर हफ्ते घटनाएं हो रही हैं। क्या यही शासन है? सुबह एक और विनाशकारी रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा-मुंबई मेल झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में पटरी से उतर गई। कई मौतें और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। यह बेहद दुखद है। हर सप्ताह रेल हादसों की दुखद शृंखला सी चल रही है। रेलवे ट्रैक पर मौत और यात्रियों के घायल होने का यह सिलसिला कब तक चलेगा? हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? टीएमसी विधायक सागरिका घोष ने भी केंद्र सरकार पर वार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ट्रेनों की सुरक्षा में अनदेखी के चलते लोगों को रोज परेशानी उठानी पड़ रही है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां हैं? वह केवल अंशकालिक रेल मंत्री हैं।

वायनाड में भूस्खलन ने निगलीं 60 जानें

» सैकड़ों के फंसे होने की आशंका, बचाव कार्य के लिए सेना बुलाई गई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोच्चि। भारी बारिश के बीच केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में हुए बड़े भूस्खलन में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत कई एजेंसियों को तैनात किया गया है। मंगलवार की सुबह भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ।

उधर प्रधानमंत्री मोदी व केरल के सीएम विजयन ने एक-दूसरे से बात की और हालात पर चर्चा की। वहीं इस हादसे को संसद में उठाया गया। ज्ञात हो कि मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से हैं। एक बयान में, भारतीय सेना ने कहा कि उन्होंने चिकित्सा टीमों सहित 225 कर्मियों को तैनात किया है। दो वायु सेना के हेलीकॉप्टर, एक एमआई-17 और एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को भी सेवा में लगाया गया है। केरल की मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि भारतीय नौसेना की एक टीम भी बचाव प्रयासों में सहायता करेगी। सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे।

पीएम ने की सीएम से बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और उन्हें संकट से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये मिलेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक बयान में कहा, वायनाड में भूस्खलन पर हर संभव बचाव अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जब से हमें घटना के बारे में पता चला है, सरकारी तंत्र बचाव अभियान में जुट गए हैं। मंत्री वायनाड का दौरा करेंगे और गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। इस बीच, भूस्खलन के मद्देनजर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया है। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9656938689 और 8086010833 भी जारी किए गए हैं। कई परिवारों को विभिन्न शिविरों या उनके रिश्तेदारों के घरों में ले जाया गया है।

यूडीएफ कार्यकर्ता बचाव और राहत कार्यों मे जुटें : राहुल

वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह भूस्खलन और इसके कारण हुई जानमाल की हानि से बहुत दुखी हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान चल रहा है। मैंने उनसे सभी एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने, एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और राहत प्रयासों के लिए आवश्यक किसी भी सहायता के बारे में हमें सूचित करने का अनुरोध किया है। मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। मैं सभी यूडीएफ कार्यकर्ताओं से बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का आग्रह करता हूं।

केशव केवल बड़बोले, उनके पास कोई काम नहीं : शिवपाल यादव

» सपा के राष्ट्रीय महासचिव बोले- सीएम ने उन्हें झुनझुना पकड़ाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। विधानभवन में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य केवल बड़बोले मंत्री हैं। उनके पास कोई काम नहीं हैं। केशव अपना विभाग ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको केवल झुनझुना पकड़ा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ की करते रहते हैं।

वहीं विधानसभा में सोमवार को सपा के बागी विधायकों की सीट बदल गई। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले ज्यादातर सपा विधायक सोमवार को पीछे की सीटों पर बैठे दिखाई दिए। सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडेय सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। उनकी भी सीट पीछे कर दी गई है। आगे बैठने वाले विधायक अभय सिंह व विनोद चतुर्वेदी भी पीछे बैठे रहे। राकेश प्रताप सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह के बगल में बैठे दिखे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट पर जहां अखिलेश यादव बैठते थे, वहां माता प्रसाद पांडेय बैठे। उनके बगल

मनोज पांडेय की अनुपस्थिति रही चर्चा का विषय

मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडेय की जगह सपा के नए मुख्य सचेतक कमाल अख्तर बैठे हुए व्यवस्था संभालते नजर आए। मनोज पांडेय करीब 12 वर्षों में पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। वहीं, राज्यसभा चुनाव में सपा का विरोध करने वाली व लोकसभा चुनाव में साइकिल से दूरी बनाने वाली पल्लवी पटेल पूर्व की तरह अपने स्थान पर ही बैठी दिखाई दीं।

में जिस सीट पर अवधेश प्रसाद बैठते थे अब वह सीट सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह यादव को आवंटित कर दी गई है।

अयोध्या में भूमि घोटाले की जांच हो : अवधेश प्रसाद

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या शहर और उसके आसपास कथित भूमि घोटाले की जांच की मांग की और दावा किया कि भाजपा ने क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। लोकसभा में बजट पर बहस में भाग लेते हुए, प्रसाद ने आरोप लगाया कि भाजपा अयोध्या के नाम पर राजनीति और व्यापार में लगी हुई है और इसलिए, शहर के लोगों ने भगवा पार्टी को खारिज कर दिया है। प्रसाद पिछले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है। उन्होंने दावा किया, बजट में अयोध्या और उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। भाजपा ने अयोध्या के नाम पर केवल राजनीति और व्यापार किया है। भाजपा ने अयोध्या के लोगों को चोट पहुंचाई है। प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा देश से सफाया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 में यूपी में और 2029 में पूरे देश में हार जाएगी।

केंद्र ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया : वांगचुक

» बोले- 15 अगस्त से फिर शुरू करेंगे भूख हड़ताल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जम्मू/लद्दाख। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र को चेतावनी दी है कि यदि सरकार लद्दाख को राज्य का दर्जा और सांविधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए लद्दाख के अधिकारियों को आमंत्रित नहीं करती है तो वह स्वतंत्रता दिवस पर 28 दिनों का उपवास शुरू करेंगे।

एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में वांगचुक ने कहा कि शीर्ष निकाय, लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। उम्मीद है कि अब वे हमारे नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। इससे पहले 27 मार्च को, वांगचुक ने 21 दिन की अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी।

भाजपा नेताओं ने शाह से की मुलाकात

भाजपा लद्दाख प्रदेश अध्यक्ष फुंचोक स्टैनजिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शाह से मिला। इसमें एलएएचडीसी लेह के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन, लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष जांस्कर स्टैनजिन लकपा, भाजपा जिला अध्यक्ष नुबरा स्टैनजिन डेलिक और भाजपा जिला अध्यक्ष कारगिल मोहम्मद अली चंदन शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख से संबंधित विभिन्न मांगें उठाईं, जिनमें लद्दाख के लिए सुरक्षा, आरक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसरों को संबोधित करना और लद्दाख के राजपत्रित पदों के लिए रिक्तियों की शीघ्र अधिसूचना, एलएएचडीसी को मजबूत करना, नए जिलों का निर्माण, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भोटी भाषा को शामिल करना, लद्दाख स्काउट्स की नई बटालियन का गठन, लद्दाख की वन्यजीव सीमाओं का युक्तिकरण, विशेष रूप से सरचू, शिंकुनला और जोजिला में अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दों का समाधान, कारगिल और नुबरा में नागरिक यात्रियों के लिए हवाई सेवाओं से संबंधित मुद्दे और लद्दाख के निरंतर विकास से संबंधित विभिन्न अन्य मामले शामिल हैं।

मुझे अदालत से इंसाफ मिला : अफजाल अंसारी

» इलाहाबाद हाईकोर्ट के सजा को रद्द करने के फैसले पर दी प्रतिक्रिया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज। गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि और उन्हें सुनाई गई चार साल की सजा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे। इस फैसले के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने कहा ये राहत नहीं उन्हें अदालत से इंसाफ मिला है।

न्यायमूर्ति एसके सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया।

इसके साथ ही, अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था।

केशव ने फिर दिखाई तल्खी, गरमाई सियासत

» बोले- चुनाव सरकार नहीं पार्टी लड़ती और जीतती है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश भाजपा के ओबीसी मोर्चा की कार्यसमिति में 'सरकार से बड़ा संगठन' के बयान से उठी सियासी उठापटक के थमने की चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने फिर से सियासी माहौल गरमा दिया है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा, कोई चुनाव सरकार नहीं पार्टी लड़ती और जीतती है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के कई नेताओं को यह अहसास तक नहीं था कि उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। यूपी के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए नुकसान की चर्चा करते हुए कहा कि जब हम सरकार में नहीं थे, तब हम जीते, लेकिन जब सरकार आ गई तो हम अति आत्मविश्वास में चुनाव हार गए। वर्ष 2014 में न तो केंद्र में हमारी सरकार थी और न ही 2017 में यूपी में। फिर भी पार्टी को जीत मिली और सरकार बनी। उन्होंने ओबीसी नेताओं को सचेत करते हुए उनको लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही उससे कभी भी प्रभावित नहीं होना है। हमें अभी से 2027 की जोरदार तैयारी शुरू कर देनी है।

अखिलेश व सपा के पतन की शुरुआत: केशव प्रसाद मौर्य

केशव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ों व दलितों को धोखा देकर के अपने पतन की शुरुआत कर ली है। वहीं, माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर कहा कि इस फैसले से अखिलेश की असलियत सामने आ गई है। यूपी में माफिया, अपराधियों व भ्रष्टाचारियों का अगर कोई सरगना है तो वे अखिलेश यादव एंड कंपनी है।

सरकार से संगठन बड़ा होता है : बृजभूषण शरण सिंह

भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। वह प्रदेश सरकार को लेकर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर इतना जरूर कहा कि अब भाजपा मुझे कोई अवसर नहीं देगी। मैं मुंगेरीलाल के सपने नहीं देखता हूं। इस समय आराम की जिंदगी जी रहा हूं। सपा मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत दी कि उन्हें भाजपा के बारे में भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा। कहा कि वह विपक्ष की भूमिका भी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल पर फूटा छात्रों का गुस्सा

» कोचिंग संस्थानों पर बुलडोजर चलना शुरू

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने चार भवन मालिकों समेत पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, दिल्ली नगर निगम ने एक कनिष्ठ अभियंता (जेई) को बर्खास्त कर दिया और एक सहायक अभियंता (एई) को निलंबित किया है, जबकि अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस थमाया है।

वहीं, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्हें छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में उपराज्यपाल ने छात्रों की बातें सुनीं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में सोमवार को निगम का बुलडोजर भी गरजा और राव कोचिंग सेंटर के पास नाले से कब्जे हटाए गए।

गृह मंत्रालय ने गठित की जांच समिति

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए समिति गठित की है। समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही, ऐसे हादसों को रोकने के उपाय भी सुझाएगी। समिति में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस कमिश्नर, फायर सलाहकार शामिल हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके संयोजक होंगे। उपराज्यपाल ने हर मृतक के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है।

सियासत के नए-नए रंग, बढ़ा रहे जंग

महाराष्ट्र-बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्ष सक्रिय

- एनडीए सरकार व बीजेपी पर जारी है वार
- कांग्रेस पूरे तेवर में , राहुल भी दिखा रहे दम
- मोदी और शाह बैकफुट पर
- राकांपा नेता अजित पवार विधानसभा चुनाव से पहले 'जन सम्मान यात्रा' शुरू करेंगे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार से लेकर बंगाल तक सियासत में नए-नए अंदाज दिखाई दे रहे हैं। कही नीति आयोग को लेकर ममता बनर्जी एनडीए की मोदी सरकार पर हमलावर है तो वहीं बिहार में राजद, व जदयू को पीके की सुराज यात्रा परेशान करने में लगी है। तो यूपी में अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडेय विस भेजने के दांव से भाजपा तो हैरान है ही मायावती भी बैचैन हो गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा में मात खाई बीजेपी व एनसीपी अजित गुट राज्य विधान चुनावों में अपनी खोए जनाधार को जुटाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। कुल मिलाकर दक्षिण से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक सियासी गणित नऐ समीकरण बनाते नजर आ रहे है। ये उतार-चढ़ाव आने वाले विस चुनावों कोई न कोई रंग जरूर दिखाएंगे।

लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार से आहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का आधार तैयार करने को लेकर जन संपर्क कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं। राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, अजित पवार के नेतृत्व में यह यात्रा नासिक से शुरू होगी। तटकरे ने नासिक में राकांपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय अजित पवार को दिया।तटकरे ने कहा कि राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल को आगामी विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता मिलेगी। भुजबल राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। राकांपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि अजितदादा पिछले 35 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हैं। उनके विरोधी उन्हें और राकांपा के अन्य नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए काम करना चाहिए। वह अजित पवार ही हैं, जिन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा कर महाविकास आघाडी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री होने के नाते अजित पवार ने राजकोषीय विवेक और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाया है। तटकरे ने कहा, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं और अन्य वर्गों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने राकांपा कार्यकर्ताओं से लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने को कहा। तटकरे ने कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली यात्रा नासिक से शुरू होकर सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी।

पुराने दलों के समीकरण बिगाड़ेगा पीके का नया दल

अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक नई राजनीतिक पार्टी का आगाज होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका 'जन सुराज' अभियान दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक दल को लाने से पहले राज्य भर की यात्रा कर चुके हैं इसलिए माना जा रहा है कि उनका यह नया दल पहले से स्थापित राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकता है। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका नया राजनीतिक दल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन सुराज की राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती सहित कई लोगों ने भाग लिया। दो साल पहले अभियान शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा, ''जैसा कि पहले कहा गया है, जन सुराज अभियान दो अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा और अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी नेतृत्व जैसे अन्य विवरण समय आने पर तय किए जाएंगे। उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी जागृति ठाकुर के जन सुराज में शामिल होने का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जन सुराज में शामिल होने वाले अन्य लोगों में पूर्व राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में अनुशासनहीनता के आधार पर विधान परिषद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी जन सुराज में शामिल हुए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद में सेवा से इस्तीफा दे दिया था लेकिन टिकट से वंचित होने के बाद उन्होंने बक्सर से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद पवन वर्मा भी जन सुराज पार्टी में शामिल हुए।

फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। अपनी पत्नी अमृता और बेटी दिविजा के साथ दिल्ली आए फडणवीस ने प्रधानमंत्री के साथ इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया।फडणवीस ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आशीर्वाद महाराष्ट्र पर हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मुझे नयी ऊर्जा और उनका मार्गदर्शन मिलता है। फडणवीस ने कहा कि वह आभारी हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया।

चुनाव से पहले सहयोगियों को साधने में लगी कांग्रेस

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए दो समितियों का गठन किया। राज्य में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। हालाँकि, भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी से दो समितियों, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी (एमआरसीसी) का गठन किया गया है। एमपीसीसी सदस्यों में नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, नितिन राउत, आरिफ नसीम खान और सतेज पाटिल शामिल हैं। मुंबई आरसीसी के सदस्य वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में नवंबर 2019 में बने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन को महाराष्ट्र में 48 में से 29 सीटें जीतकर एक मजबूत मौका मिला। दो दलों के भीतर विभाजन, प्रमुख हस्तियों द्वारा दलबदल और प्रमुख नेताओं से जुड़े कानूनी मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, विपक्षी गठबंधन में तीन दलों का प्रदर्शन इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) ने सीट-बंटवारे समझौते के तहत आवंटित दस सीटों में से आठ पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने भाजपा से विदर्भ का नियंत्रण लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार किया, 2019 में अपनी सीटें एक से बढ़ाकर 2024 में 13 कर लीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना-यूबीटी ने राज्य में 21 में से केवल नौ सीटें जीतीं। समाजवादी पार्टी (सपा), जो विपक्षी भारत गुट का हिस्सा है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के हिस्से के रूप में आगामी विधानसभा चुनावों में लगभग 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है।

नीति आयोग पर राजनीति, विपक्ष का बहिष्कार करना पुरानी बात

इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे। चूंकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आईं तो, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहेंगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई हों, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकती हैं, जिससे वह चर्चा में आ जाएं। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी हैं या फिर उसमें किसी न किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी हैं। यदि उन्होंने सोची-समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो तो हैरानी नहीं। हो सकता है कि वह मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हों कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे, जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से हासिल क्या हुआ? यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं, जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहां तक कि राष्ट्र हित के विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया, क्योंकि बजट में विपक्ष शासित राज्यों की कथित तौर पर अनदेखी की गई है। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है और फिर यदि उन्हें ऐसा ही लगता है तो उन्होंने अपनी बात नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर गंवाना क्यों पंसद किया?

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

किसान हित के लिए एकमत होना जरूरी

लोकसभा में बजट सत्र की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है। साथ उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष की किसानों के लिए चिंता उचित है। अब सरकार को भी चाहिए कि किसानों के लिए बजट से हटकर कुछ करें ताकि किसानों की आय तो दोगुनी हो ही साथ उनका जीवन स्तर भी उठ सके। केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है।

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। अब ये सरकार व विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के लिए एकमत हो और एक साझा सुझाव व सहमति से उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं।

अब सरकार को भी चाहिए कि किसानों के लिए बजट से हटकर कुछ करें ताकि किसानों की आय तो दोगुनी हो ही साथ उनका जीवन स्तर भी उठ सके। केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी

ज्योति मल्होत्रा

शुक्रवार के दिन कारगिल विजय स्मृति स्मारक पर आयोजित समारोह के टेलीकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े देखा, जैतूनी हरे रंग के बंद-गला कोट और हल्के भूरे लेंस का रंगीन चश्मा लगाकर खूब जंच रहे थे, अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान द्वारा सीमा पारीय आतंकवाद को निरंतर शह और मदद देते रहने के लिए लताड़ा- कारगिल युद्ध हुए 25 साल गुजर गए, स्पष्टत: कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदलीं। लेकिन यहां चंडीगढ़ में, बजट दस्तावेज बांचने का काम हमारा इंतजार कर रहा था। एक बारगी लगा कि 'स्वास्थ्य' और 'शिक्षा' वाले हिस्से इससे गायब हैं। हो सकता है, रिसकर उस भाग में चले गए हों जो शेयर मार्केट में निवेश पर अर्जित मुनाफे पर कर की बाबत है- वह एक कैटेगरी, जिस पर हफ्ते के शुरू में पेश बजट के बाद से भारतीय शेयर मार्केट के दीवानों ने सावधानी से नजर रखी।

गौरतलब है कि जिस क्षण सुश्री सीतारमण ने कर लगाने की बात कही, बाजार की प्रतिक्रिया कुछ गुस्से भरी दिखी। लेकिन हर कोई जानता है कि मंगलगिरी साड़ी पहने शांत छवि वाली निर्मला दृढ़ इच्छाशक्ति संपन्न महिला हैं, वे वहां पहुंच रही हैं, जहां कोई फरिश्ता और यहां तक कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम भी जाने का साहस न करते। उन पर 'रोलबैक वित्त मंत्री' का ठप्पा लगने से रहा। इससे हमारे लिए एक अन्य सवाल उठ खड़ा होता है : अपना पुनर्गठन, परिवर्तन और आधुनिकीकरण किए जाने को तरस रहे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को निर्मला सीतारमण ने क्योंकर नजरअंदाज किया? पुरुष वर्चस्व वाली राजनीतिक पार्टी में इतने उच्च स्तर पर पहुंचना, उससे पहले जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त निर्मला ने भूसे से गेहूं के दाने अलग करना या फिर बुरे और अच्छे व्यवहार बीच फर्क करने की कला अच्छी तरह सीख ली थी (मसलन, अपनी पूर्व मंत्रिमंडल सहयोगी स्मृति ईरानी की तरह वे अपने मातहत अफसरों पर फाइलें फेंककर नहीं मारती, जैसा कि मानव संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर किया)। इसके अधिक, वे डाटा की कद्र है, भले ही यह साफ तौर पर छिपाने की गर्ज से हो।

उदाहरण के लिए उन्हें मालूम है कि बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच तुलना करना नितांत गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं -पहले वाला, अनुमानित खर्च की बाबत है तो

दूसरा वास्तव में किए जाने वाले खर्च के बारे में है। इसलिए, पिछले साल के बजटीय अनुमान और मौजूदा साल के संशोधित अनुमानों की तुलना के आधार पर यह कहना एकदम गलत है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखे धन में 12 फीसदी इजाफा किया गया है। यह सेब की तुलना संतरे से किए जाने जैसा है। सही चीज होती, मौजूदा और पिछले साल के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना करना। पिछले साल के लिए यह 89,155 करोड़ रुपये था जो मामूली बढ़ोतरी (1,803.63 करोड़) अर्थात 1.98 फीसदी वृद्धि के साथ इस साल 90,958.63 करोड़ रुपये किया गया। इसके अलावा, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए खर्च में बढ़ोतरी शोचनीय 1.16 फीसदी है वहीं प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना में इजाफा महज 1.4 प्रतिशत है। जबकि इसके लाभार्थी वे 55 करोड़ लोग हैं, जिनका हिस्सा कुल जनसंख्या का लगभग 40 फीसदी है- उपरोक्त वर्णित दोनों योजनाएं वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी आयुष्मान भारत नामक अग्रणी स्वास्थ्य परियोजना का मुख्य अवयव हैं। तो बजटीय प्रावधान में राशि में की गई इस नगण्य बढ़ोतरी के बूते किस तरह 2025 तक देश से टीबी का खात्मा करने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा या सब बच्चों में रोग-प्रतिरोधकता बनाना या फिर लड़कियों एवं महिलाओं में गर्भाशय कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन जारी करने का ध्येय कैसे पूरा होगा- जबकि फरवरी माह में पेश अंतरिम बजट में अंतिम हेतु वादा किया गया था? फिर यहां कोरा सच है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय खर्च पहले की भांति जीडीपी का महज 1.9 प्रतिशत बना हुआ है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में तय किये गए लक्ष्य यानी 2.5 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है। कोविड-19 महामारी, जिसमें भारत को बहुत जान-माल का भारी नुकसान हुआ (आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 5,32,000 बताई गई) के बाद लगता था कि जरूर इससे कुछ सबक लिए होंगे।

शिक्षा क्षेत्र का आलम भी कुछ अलग नहीं है। पिछले साल के लिए बजटीय अनुमान 1,12,899.47 करोड़ रुपये था, जो इस साल मामूली बढ़ोतरी (7,728.4 करोड़) के साथ 1,20,627.87 करोड़ रुपये किया गया। आर्थिक सर्वे के मुताबिक, जीडीपी के अंश के तौर पर शिक्षा के लिए रखा फंड दरअसल 2.8 प्रतिशत से घटकर 2.7 फीसदी होने के साथ वर्ष 2010 के स्तर पर जा पहुंचा है (जबकि यूनेस्को द्वारा तय वैश्विक मानक 4-6 प्रतिशत है)।

भारत की ताकत रही है धार्मिक विविधता

विश्वनाथ सचदेव

शेक्सपियर तो लिख गये कि क्या रखा है नाम में, पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ नाम का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश निकाला था कि कांवड़ियों की यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली खाने-पीने के समान की सभी दुकानों, रेहड़ी वालों, ठेले वालों को अपनी दुकान के बाहर मालिक का, और वहां काम करने वाले सभी लोगों का, नाम लिखकर लगाना होगा, ताकि उन दुकानों आदि से सामान खरीदने वालों को यह पता रहे कि वह किस धर्म को मानने वाले से सामान खरीद रहे हैं! तर्क यह दिया जा रहा है कि सवाल कांवड़ियों की आस्था की शुचिता का है! लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यह वार्षिक यात्रा, या देशभर में इस तरह की धार्मिक यात्राएं तो न जाने कब से चल रही हैं, आज तक तो किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंची, फिर अचानक कांवड़ियों को लेकर यह विवाद क्यों?

प्रशासन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि यह सब 18 साल पहले के एक कानून के अनुसार किया जा रहा है। तत्कालीन सरकार ने इस आशय का कानून पारित किया था, जो अब लागू किया जा रहा है, इसलिए इसे लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन विवाद हो रहा है, सड़क से लेकर संसद तक, और उच्चतम न्यायालय में भी विवाद की गूंज पहुंची है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर विवाद नहीं छिड़े। इस संदर्भ में बहुत कुछ अप्रिय हुआ है देश में, हिंदू और मुसलमान को लेकर अक्सर सवाल उठाये जाते रहे हैं। कभी पूजा स्थल को लेकर, कभी पूजा-अर्चना की पद्धति को लेकर और कभी कथित धार्मिक पहनावे के नाम पर अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में सांप्रदायिकता की आग भड़कायी गयी है। सवाल नाम से पहचान का भी नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने में विश्वास करती है। उस घटिया राजनीति का है जो धर्म के नाम पर वोट मांगने में किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं करती। अभी हाल में बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा करने में तनिक हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि हमें (अब) 'सबका साथ, सबका विकास' की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने बंगाल की एक सभा में यह कहना जरूरी समझा कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट करना जरूरी समझा कि भाजपा को अपना अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। यह बात दूसरी है कि इस 'गर्जना' के कुछ ही घंटे बाद उन्हें शायद भाजपा आलाकमान के आदेश पर यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनके कहने का गलत अर्थ लगाया गया है। था कोई जमाना जब राजनेता अक्सर यह कहकर बच निकलते थे कि उन्हें गलत उद्धृत किया गया, अथवा गलत समझ गया, पर चौबीस घंटे समाचार चैनलों के युग में यह बहानेबाजी नहीं चल सकती। सारी दुनिया ने शुभेंदु अधिकारी के उस भाषण को सुना है। दुनिया ने तो भाजपा के एक अन्य बड़े नेता को पिछले चुनावों के समय प्रचार के दौरान यह कहते भी सुना था कि हमें अल्पसंख्यकों के वोट की आवश्यकता नहीं है।

यही क्यों, स्वयं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह कह चुका है कि कांग्रेस वाले देश के संसाधन मुख्यत: 'ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों' को देना चाहते हैं। यह सारी बातें सांप्रदायिकता की उस घटिया और खतरनाक राजनीति की ओर इशारा करती हैं जो देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर बनाने में लगी है। हमारा पंथ-निरपेक्ष संविधान सर्व धर्म समभाव में विश्वास करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-विचार कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से इनकार किया था। आसेतु-हिमालय हमारा भारत सभी धर्मों को मानने वाले भारतवासियों का देश है। हमारे प्रधानमंत्री यह कहते नहीं थकते की 140 करोड़ भारतवासी उनका परिवार है। जब इस परिवार के एक हिस्से को पंक्ति से बाहर बिठाने की कोशिशें हो रही हैं तो स्वयं को परिवार का मुखिया मानने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इन विघटनकारी गतिविधियों का न केवल विरोध करे बल्कि उन्हें असफल बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करे। दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री को तब विरोध करना चाहिए था जब सबका साथ, सबका विकास के उनके नारे को नकारा गया। बंगाल के उस भाजपाई नेता के कथन पर भाजपा का कोई बड़ा नेता कुछ नहीं बोला, यह बात रेखांकित होनी चाहिए। यह भी रेखांकित होना चाहिए कि कांवड़ियों की आस्था की पवित्रता के नाम पर देश में अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है।

न्यायालय ने अपने विवेक से इस बारे में उचित निर्णय लिया। लेकिन एक निर्णय इस देश की जनता को भी लेना है— उन सारी ताकतों को असफल बनाने का निर्णय जो हमारी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने पर तुली हैं। हमारी गंगा-जमुनी सभ्यता ने हमें एक ऐसे समाज के रूप में विकसित होने का अवसर दिया है जहां मनुष्य को उसकी धार्मिक आस्था के आधार पर चिन्हित किए जाने का कोई स्थान नहीं है। यही हमारा वह संविधान भी कहता है जिसकी शपथ हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि लेते नहीं थकते। शपथ लेना ही पर्याप्त नहीं है, शपथ के विश्वास को प्रमाणित करना भी जरूरी है। यह काम कथनी और करनी की एकरूपता से ही हो सकता है। संविधान को माथे से छुआने से नहीं, उसके अनुरूप आचरण करने से संविधान के प्रति निष्ठा प्रमाणित होती है। कांवड़ियों की आस्था की पवित्रता की दुहाई देने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए की यात्रा के मार्ग में कांवड़ियों का स्वागत-सत्कार करने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं हैं।

चाय के साथ इन पकौड़ों का लें आनंद

बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई है। कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश की वजह गर्मी के मौसम ने भी करवट बदल ली है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को काफी राहत मिली है। बारिश के इस खुशनुमा मौसम में घूमने और कुछ चटपटा खाने का मन तो हर किसी का करता है। खासतौर पर बात करें पकौड़ों की, तो इस मौसम में बारिश आते ही हर किसी से जहन में अदरक वाली चाय और पकौड़ों की तस्वीर घूमने लगती है। ज्यादातर लोग बारिश में प्याज और आलू के पकौड़े खाना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में प्याज-आलू के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ अलग ट्राई करें। आप प्याज और आलू को छोड़ कर कई अन्य सब्जियों की मदद से भी स्वादिष्ट पकौड़े बना सकते हैं।

पनीर पकौड़े

पनीर का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी के तौर पर ही नहीं किया जाता है बल्कि इससे कई तरह के अन्य फूड आइटम्स भी तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से ही एक स्वाद से भरा फूड आइटम है पनीर पकोड़े का चाय के साथ पनीर के पकौड़े खाने में काफी स्वादिष्ट लगते हैं। इसे बनाना काफी आसान होता है। पनीर के पकौड़े ज्यादा तीखे नहीं होते, इसलिए आप इसे इसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसे हरे धनिए की चटनी के साथ ही परोसें।

मूंग दाल के पकौड़े

दिल्ली की सड़कों पर आपको मूंग दाल के पकौड़े आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसे घर पर बना कर बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरे धनिए की तीखी चटनी खाने में और स्वादिष्ट लगती है।

मिर्च पकौड़े

बड़ी वाली मिर्च क स्वादिष्ट पकौड़े राजस्थान की काफी पॉपुलर डिश है। आप चाहें तो इसे घर पर आसानी से बना सकती हैं। ध्यान रखें कि मिर्च के पकौड़े बनाते समय मिर्च पर बेसन की लेयर को ज्यादा मोटा न रखें, इससे इसका स्वाद खराब हो सकता है। यह पकौड़े बाहर से क्रिस्पी और इनके अंदर आलू की स्टफिंग होती है। इन्हें आप हरी चटनी या फिर चाय के साथ सर्व किया जाता है। बारिश के मौसम में इन पकौड़ों का खाने का मजा ही अलग है।

कटहल के पकौड़े

कटहल की सब्जी तो ज्यादातर लोगों को पसंद आती है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कटहल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। कटहल के बने कुरकुरे पकौड़े खाने में काफी स्वादिष्ट लगते हैं। जिन लोगों को इसकी सब्जी नहीं पसंद वो भी पकौड़े को बड़े मन से खाएंगे। कटहल में पोटैशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कटहल में कई फलों से ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स है।

बैंगन के पकौड़े

इस मौसम में बैंगन काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। आपने बैंगन की सब्जी तो कई बार खायी होगी लेकिन क्या कभी बैंगन के पकोड़ों का स्वाद चखा है? ऐसे में आप चाहें तो बैंगन के पकौड़े बनाकर अपने घरवालों का दिल जीत सकती हैं। जिन लोगों को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं आती, वो भी इसे बड़े चाव से खाएंगे।

कद्दू के फूल के पकौड़े

कद्दू के फूल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। खाने में ये काफी स्वादिष्ट लगते हैं। ये बंगाल और ओडिशा में ये एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। अगर आपके घर के आस-पास भी कद्दू के फूल आसानी से मिल जाते हैं तो इस पकौड़े को जरूर बनाकर ट्राई करें। कद्दू के फूलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद करता है। इस वजह से हम सर्दी और खांसी जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं।

हंसना मना है

भाभी जी- भैया, ये आम लंगड़ा है क्या? फलवाला- हां भाभी, भाभी जी- लेकिन सभी एक जैसे दिख रहे है, मैं कैसे मानूं? फलवाला- लंगड़ा है तभी तो ठेले पर बिठाकर घुमा रहा हूं। फलवाले की बात सुन भाभी जी बेहोश।

सास- दामाद जी अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? दामाद- अगले जन्म में छिपकली बनना चाहुंगा। सास- छिपकली? वो क्यूं? दामाद- क्योंकि आपकी बेटी छिपकली से बहुत डरती है।

संता बड़ा परेशान था, बेचारे की शादी जो नहीं हो रही थी। हर बार शादी होते-होते टूट जाती। बेचारा एक दिन एक पंडित जी के पास पहुंच गया। और बोला- पंडित जी कोई उपाय बताए मेरी शादी नहीं हो रही हमेशा टूट जाती है। पंडित जी ने कहा- शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद करो।

शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये देख रहा था, उसने अपने पिता से पूछा - पिताजी दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया - बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं।

कहानी | बुराई का अंत हर हाल में होता है

एक सांप को एक बाज आसमान पे ले कर उड़ रहा था। अचानक पंजे से सांप छूट गया और कुवें में गिर गया बाज ने बहुत कोशिश की अखिर थक हार कर चला गया। सांप ने देखा कुवें में बड़े बड़े किंग साईज़ के मेढ़क मौजूद थे। पहले तो डरा फिर एक सूखे चबूतरे पर जा बैठा और मेढ़कों के प्रधान को लगा खोजने। अखिर उसने एक मेढ़क को बुलाया और कहा मैं सांप हूं मेरा जहर तुम सब को पानी में मार देगा। ऐसा करो रोज एक मेढ़क तुम मेरे पास भेजा करो, वह मेरी सेवा करेगा और तुम सब बहुत आराम से रह सकते हो। पर याद रखना एक मेढ़क रोज आना चाहिए। एक-एक कर के सारे मेढक सांप खा गया। जब अकेले प्रधान मेढ़क बचा तब सांप चबूतरे से उतर कर पानी में आया और बोला प्रधान जी आज आप की बारी है। प्रधान मेढ़क ने कहा मेरे साथ विश्वास घात हुआ है। सांप बोला जो अपनों के साथ विश्वास घात करता है उसका यही अंजाम होता है। फिर उसने प्रधान जी को गटक लिया। कुछ देर के बाद सांप आहिस्ता आहिस्ता कुवें के ऊपर आ कर चबूतरे पर लेट गया। तभी एक बाज ने आकर सांप को दबोच लिया और बोला पहचान सांप मुझे मैं वही बाज हूं जिसके बच्चे तूने पिछले साल खा लिये थे। और जब तुझे पकड़ कर ले जा रहा था तब तू मेरे पंजे से छूट कर कुएं में जा गिरा था। तब से मैं रोज तेरी हरकत पर नजर रखता था। आज तू सारे मेढ़क खा कर काफी मोटा हो गया। मेरे फिर से बच्चे बड़े हो रहे हैं वह तुझे जिंदा नोच-नोच कर अपने भाई बहनों का बदला लेंगे। फिर बाज सांप को लेकर उड़ गया अपने घोसले की तरफ।

कहानी से सीख- हमें इस कहानी यह सीख मिलती है कि बुराई एक दिन हार ही जाती है वह चाहे कितनी भी ताकतवर हो!

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी न करें। लेनदारी वसूल करने के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी।

वृषभ

नई आर्थिक नीति बन सकती है। कार्यस्थल पर सुधार व परिवर्तन से भविष्य में लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग कार्य में गति प्रदान करेगा।

मिथुन

लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में उन्नति होगी। निवेशादि करने का मन बनेगा।

कर्क

धनागम होगा। प्रतिद्वंद्वी अपना रास्ता छोड़ देंगे। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। किसी भी प्रकार के झगड़ों में न पड़ें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

सिंह

रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सभी ओर से खुश खबरें प्राप्त होंगी। पारिवारिक चिंता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा।

कन्या

ऐश्वर्य के साधनों पर व्यय होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

तुला

लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में संतोष रहेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा।

वृश्चिक

किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है।

धनु

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। पराक्रम बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

मकर

घर में अतिथियों का आगमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा। बाहर जाने का मन बनेगा।

कुम्भ

अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। नौकरी में प्रमोशन? मिल सकता है। सुख के साधनों पर व्यय होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

मीन

व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। हल्की हंसी-मजाक न करें।

बॉलीवुड | मन की बात

बेटी राहा की वजह से मैंने सिगरेट छोड़ा : रणवीर कपूर

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बी टाउन के पॉपुलर कपल हैं। रणबीर ने हाल ही में इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि बेटी राहा के जन्म के बाद से ही उनकी लाइफ में काफी बदलाव आया है। राहा के जन्म के बाद रणबीर ने अपनी पुरानी बुरी आदत को छोड़ दिया है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में बोला कि- अब मैं एक पिता हूं और मेरी एक बेटी है। इस बात ने मेरी लाइफ को बदल दिया है। पिता बनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ है। मुझे लगा था कि 40 साल तक मैं दूसरी लाइफ जी रहा था। मेरी बेटी के साथ मुझे दूसरा जीवन मिला है। रणबीर ने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने बेटी राहा के लिए अपनी बुरी आदत को छोड़ दी है। एक्टर ने बताया कि वह 17 साल की उम्र से सिगरेट पी रहे थे। एक्टर को सिगरेट पीने की बुरी लत लगी थी, लेकिन पिता बनने के बाद पिछले साल उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। एक्टर ने आगे बोला- मुझे पहले से बहुत ज्यादा फिट महसूस हो रहा है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि राहा की वजह से उन्होंने सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया। रणबीर ने बोला एक पिता के रुप में अपनी नई जिम्मेदारियों का एहसास ने ही सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया ताकि उनकी बेटी स्वस्थ रह सकें।

रिलीज से पहले ही छा गई 'उलझ'

जाह्नवी कपूर अपनी अगली मिस्ट्री मूवी 'उलझ' की रिलीज को तैयार हैं। फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज से पहले निर्माताओं ने जाह्नवी कपूर के फैंस के लिए खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसे अब जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म की टीम ने ऑफिशियल रिलीज से पहले कई शहरों में विशेष प्रिव्यू स्क्रीनिंग की घोषणा की थी, जिसकी टिकटें सिर्फ 30 मिनट में बिक गई।

जाह्नवी कपूर की किसी फिल्म के लिए पहली बार मेकर्स रिलीज से पहले कई शहरों में उनके फैंस के लिए विशेष प्रिव्यू स्क्रीनिंग को होस्ट करेंगे। जाह्नवी कपूर ने सोशल मीडिया पर फैन स्क्रीनिंग की जानकारी दी, जो 29 जुलाई को मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में होस्ट होने जा रहे हैं। 'उलझ' का प्रीमियर 2 अगस्त को होने वाला है। प्रिव्यू स्क्रीनिंग की टिकटें 27 जुलाई को टिकटिंग आउटलेट्स पर उपलब्ध कराई गई थी और 30 मिनट के भीतर ही बिक गईं। जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने पर निर्माताओं ने तीन और शहरों में फैन स्क्रीनिंग करवाने का फैसला किया।

सस्पेंस से भरपूर है फिल्म 'उलझ'

फिल्म का ट्रेलर काफी इंटेंस है, जिसमें जाह्नवी, गुलशन और रोशन बेहतरीन अभिनय करते नजर आ रहे हैं। हर एक किरदार का स्याह पहलू है, जो फिल्म सस्पेंस और ट्विस्ट से भर देते हैं। फिल्म में आदिल हुसैन, राजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र जोशी भी हैं। यह फिल्म सुधांशु सरिया और परवीज शेख द्वारा लिखी गई है। फिल्म को सुधांशु सरिया ने निर्देशित किया है।

डिप्लोमेट के रोल में हैं जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर ने अपना उत्साह जताते हुए कहा, 'मैं यह बताते हुए रोमांचित हूं कि हमने कई शहरों में फैंस के लिए 'उलझ' के लिए खास प्री-रिलीज स्क्रीनिंग रखी है। यह मेरी पहली फिल्म होगी, जिसे रिलीज होने से पहले फैंस को दिखाई जाएगी। खास बात यह है कि शो इतनी जल्दी बुक हो जाते हैं। रोमांच यकीन से परे है।' फिल्म में, जाह्नवी कपूर ने सुहाना का किरदार निभाया है, जो एक युवा डिप्लोमेट है जो लंदन दूतावास में अपने काम के दौरान एक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से फंस जाती हैं।

टीवी पर लंबे वक्त बाद कमबैक करने पर बरखा बिष्ट ने फैंस का जताया आभार, बोलीं-

'टेलीविजन मेरे लिए हमेशा से ही घर जैसा रहा'

बरखा बिष्ट कुछ समय से टेलीविजन से दूर थीं, लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक्ट्रेस बरखा ने कहा, 'टेलीविजन मेरे लिए हमेशा से ही घर जैसा रहा है। यह एक ऐसी जगह है, जहां मैं सही मायनों में अपने दर्शकों से सही से जुड़ सकती हूं। साथ ही, अपने किरदारों को जीवंत कर सकती हूं। भले ही मैं कुछ समय टेलीविजन से दूर रही हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने टेलीविजन छोड़ दिया है।'

एक्ट्रेस फिलहाल फैमिली ड्रामा 'मेरा बालम थानेदार' में अभिनय कर रही हैं, जिसमें वह मीठी माई की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म 'मेरा बालम थानेदार' में अपनी भूमिका के बारे में बरखा ने बताया, 'मीठी माई का किरदार निभाना एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव रहा है। अपने इस किरदार के प्रति मेरा एक खास नजरिया है। यह जर्नी प्यार, चुनौतियों और अविश्वसनीय पलों से भरी हुई है, जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगी।'

एक्ट्रेस ने बताया कि उनका किरदार श्रुति चौधरी और शगुन पांडे के किरदार बुलबुल और वीर के जीवन में कई उतार-चढ़ाव लाएगा। वे आगे बोलीं, 'मुझे लगता है कि ये उतार-चढ़ाव दर्शकों को शो से जोड़े रखते हैं। इस भूमिका ने मुझे न केवल अपने अभिनय के नए पहलुओं को तलाशने का मौका दिया, बल्कि दर्शकों के दिलों में जगह बनाने का मौका दिया है।' उन्होंने कहा कि वह अपने दर्शकों के सपोर्ट और स्नेह के लिए आभारी हैं, जो उन्हें हर दिन अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करते हैं। शो 'मेरा बालम थानेदार' कलर्स पर प्रसारित होता है।

'कितनी मस्त है जिंदगी' से शुरू किया था करियर

बरखा बिष्ट के बेहतरीन डांसर भी हैं। उन्होंने टीवी शोज के अलावा रियलिटी शो का भी हिस्सा रही हैं। वे हिंदी और बंगाली फिल्मों और टीवी शो में काम करती रही हैं। उन्होंने साल 2004 में एकता कपूर की टीवी सीरीज 'कितनी मस्त है जिंदगी' से करियर शुरू किया था। सीरीज में उनके कोस्टार करण सिंह ग्रोवर, मानसी पारेख और पंछी बोरा थे। उनके पिता भारतीय सेना में कर्नल थे।

अजब-गजब | महज ढाई घंटे में पहुंच जायेंगे इस राज्य के एक छोर से दूसरे तक

इसे माना जाता है देश सबसे छोटा राज्य

भारत एक विविधता भरा देश है। कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश वाले इस देश में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग संस्कृति और भाषाएं हैं। इसके अलावा देश के अलग हिस्सों में मौसम भी बिल्कुल अलग है। दिल्ली में जहां गर्मी पड़ती है तो हिमाचल, कश्मीर सहित नॉर्थ-ईस्ट वाले राज्यों में मौसम में ठंडक बरकरार रहती है। कोई राज्य जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो कोई क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में शुमार है। लेकिन क्या आप देश के सबसे छोटे राज्य के बारे में जानते हैं? यकीनन, बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। पहली बार में ज्यादातर लोगों को केरल या फिर नॉर्थ-ईस्ट के किसी राज्य का नाम जेहन आएगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है।

दरअसल, देश के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह इतना ज्यादा छोटा है कि आप उस राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक महज ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी अन्य राज्यों की बात करें, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक शामिल है, अगर आपको किसी एक छोर से इन राज्यों की राजधानी तक जाना पड़े तो कुल 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि फिर वो कौन-सा राज्य है, जो

इतना छोटा है। ऐसे में बता दें कि ये राज्य अपने खूबसूरत समुद्री बीचेस के लिए जाना जाता है। साथ ही यहां नाइट लाइफ भी बेहद मजेदार है। समुद्री बीच के अलावा कई ऐसी जगहें भी हैं, जहां पर टूरिस्ट घूम सकते हैं। इस राज्य का नाम गोवा है।

गोवा को देश का सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा प्राप्त है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 स्क्वैयर किलोमीटर है। दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसका क्षेत्रफल 7 हजार 96 स्क्वैयर किलोमीटर है। इन दोनों के अलावा त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम भी छोटे राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि देश के पांच सबसे छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम शुमार हैं। बात गोवा की बात करें तो एक छोर पर पतरादेवी से दूसरे छोर पर पोलम बीच तक की दूरी 123 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप कार से 2 घंटे 40 मिनट में पूरी कर सकते हैं।

गोवा न सिर्फ क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य है, बल्कि जनसंख्या के हिसाब से भी चौथा सबसे छोटा राज्य है। हालांकि, खूबसूरत बीच की वजह से दुनियाभर से टूरिस्ट यहां घूमने के लिए आते हैं। यहां पर आप भागा बीच से लेकर अंजुना और वागाटोर बीच पर जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई खूबसूरत बीचेस यहां पर हैं, जहां समुद्री लहरों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप बस्तरिया मार्केट से आर्ट से जुड़ी चीजें और फैशनेबल कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर बॉम चर्च भी है, जो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके अलावा दूधसागर फॉल को भी घूम सकते हैं, जिसे देखना एक अनोखा अनुभव है।

इस शहर में बन रहे हैं पक्षियों के लिए डेढ़ लाख फ्लैट

विश्व प्रशिद्ध बाबा महाकाल की नगरी जिसे धार्मिक नगरी नाम से जाना जाता है। यहा दान पुण्य के साथ जीव-जंतुओं व पशु-पक्षी की सेवा भी की जाती है। पेड़ों की कटाई और हवा-आंधी से पेड़ों के गिरने से पंछियों के रहने की जगह खत्म होने पर उज्जैन सिंधी समाज की ओर से एक नई पहली शहर मे देखने को मिल रही है। ये है पक्षियों का नया आशियाना पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बसंत विहार पार्क के बाद अब उज्जैन-सांवेर रोड पर वार्ड 47 में मुनिनगर तालाब के समीप करीब 52 फीट ऊंचा नया पक्षी घर बनाया गया है। इसमें एक साथ 3000 से ज्यादा पक्षी रह सकेंगे। इसी में उनके लिए दाना-पानी आदि का इंतजाम भी रहेगा।

इस पक्षी के आशियाने की कीमत की बात करे तो करीब 7.50 लाख रुपए का खर्च आया है। जिसका पूरा खर्चा उज्जैन के सिंधी ने किया है। इसके साथ ही अब उज्जैन में कुल चार पक्षी घर हो गए हैं। सिंधी समाज के इस निर्णय के तहत अब 46 पक्षी घर और बनाए जाएंगे। इससे उज्जैन में पक्षी घरों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। गोपाल बलवानी ने बताया मुनिनगर में पक्षी घर बनकर तैयार हो गया है। इसका विधिवत शुभारंभ कर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जिससे हजारों पक्षियों को नया घर मिलेगा। इसी घर में पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था भी रहेगी। बता दें कि महाकाल कि नगरी मे पहला पक्षी घर गुजरात के मोरवी के श्रीराम कबूतर घर ट्रस्ट की ओर से मंगलनाथ मंदिर के समीप करीब बाद 55 फीट ऊंचा बनाया जा चुका है। इसके उज्जैन में पक्षी घर बनाने की शुरुआत हुई। यह ट्रस्ट गुजरात में पक्षी घर बना चुका है। अब यह ट्रस्ट 12 ज्योतिर्लिंगों पर पक्षी घर बनाने में जुटा है।

कर्नाटक को बदनाम कर रही भाजपा : सिद्धारमैया

बोले- झूठ बोल रहीं हैं निर्मला सीतारमण

» विशेष अनुदान की धनराशि कहां गई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री पर कर्नाटक को बजट आवंटन के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य के साथ वित्तीय अन्याय कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा कर्नाटक को भ्रष्ट राज्य के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है और सभी को मिलकर राज्य के साथ हुए अन्याय का विरोध करना चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि सीतारमण कह रही हैं कि कोई अन्याय नहीं हुआ है। जब भी निर्मला सीतारमण कर्नाटक में आई हैं, उन्होंने झूठ बोला है।

उन्होंने पहले भी झूठ बोला है, अब भी वह झूठ बोल रही हैं। मुख्यमंत्री रविवार को सीतारमण की टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, जहां उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया था कि कर्नाटक को इस साल केंद्रीय बजट में अपना उचित हिस्सा नहीं मिला। सिद्धारमैया ने कर्नाटक को किए गए 5,300 करोड़ के बजट पूर्व वादे और राज्य में अपर भद्रा परियोजना जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन आवंटित न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विशेष अनुदान के रूप में 5,495 करोड़ की सिफारिश की है, क्या यह वहां है? यह कहा गया था कि परिधीय रिंग रोड के लिए 3,000 करोड़ दिए जाएंगे। कहां है। जल निकायों का विकास, क्या यह बजट में है? सिद्धारमैया ने आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे एनडीए सहयोगी राज्यों को अनुदान आवंटन का भी हवाला दिया, जबकि सवाल उठाया कि कर्नाटक को इतना आवंटित क्यों नहीं किया गया।

हरियाणा में सरकार बनने पर पदक विजेता बनेंगे उच्च अधिकारी : हुड्डा

रोहतक। हरियाणा लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने खिलाड़ियों को लेकर बड़ा एलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से खिलाड़ियों के लिए 'पदक लाओ, पद पाओ' नीति को लागू किया जाएगा। खिलाड़ियों को नौकरियों में तीन प्रतिशत कोटा देकर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। हुड्डा सोमवार को अपने डी पार्क स्थित आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान गांवों में सैकड़ों खेल स्टेडियम बनाए गए थे, लेकिन भाजपा ने उनका रख-रखाव तक ढंग से नहीं किया।

मप्र में बिना रीडिंग ग्रामीणों को थमा रहे भारी भरकम बिल : पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरा प्रदेश बारिश से तरबतर हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में अव्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और बिजली संकट की बात की जाये तो पूरा प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है, बावजूद उसके शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिना जांच और बिना रीडिंग किये भारी भरकम बिल जनता को थमाये जा रहे हैं। तानाशाही इतनी कि बिल न भरने पर किसानों के खेत और घरों में रखा सामान, ट्रैक्टर ट्राली, मोटर साईकिल तक जप्त कर लिये जाते हैं। पटवारी ने कहा कि अपने आप को किसानों की हिमायती बताने वाली भाजपा सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों में खौप का माहौल व्याप्त है। बुंदेलखंड और खासकर रायसेन जिले की स्थित बिजली को लेकर बेहाल है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली मुहैया करायी थी।

बीजेपी ने गेम चेंजर का किया वादा लेकिन बन गई नेम चेंजर : पटनायक

» बोले- बजट में कई स्कीम्स के लिए जरूरी फंड नहीं दिए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भुवनेश्वर। कांग्रेस के बाद अब बीजू जनता दल (बीजेडी) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर उनके मेनिफेस्टो की बातों को कॉपी करने का आरोप लगाया है। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने बजट पेश किया। इसमें प्रावधानों को लेकर पूर्व सीएम और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने निशाना साधा है। पटनायक ने कहा, भाजपा ने सत्ता में आकर गेम चेंजर का वादा किया था, लेकिन वो नेम चेंजर बन गई है।

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इलेक्शन मेनिफोस्टो में कई स्कीम्स के लिए बजट देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन चरण माझी सरकार ने अपने बजट में कई स्कीम्स के लिए जरूरी फंड नहीं दिए है। ओडिशा विधानसभा में पेश किए गए बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने कहा, बीजेपी ने बजट में बीजद सरकार के समय में लाए गए 45 स्कीम्स के नाम बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 25 जुलाई को राज्य सरकार का पहला बजट पेश किया था।नवीन पटनायक ने कहा,बीजेपी ने कहा था कि उनकी सरकार गेम चेंजर बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार नेम चेंजर बन गई है। बीजेपी ने नाम और रंग बदलकर पुराना बजट पेश किया है। नवीन पटनायक ने कहा, सरकार ने सुभद्रा स्कीम के लिए पर्याप्त बजट का अलॉटमेंट नहीं किया है। इस स्कीम को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। लेकिन बजट में सिर्फ 10 हजार करोड़ अलॉट किया गया है।

राजस्थान में बढ़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर तेजी से अपराध : गहलोत

» बीजेपी राज में पुलिस नाकाम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं तथा मुख्यमंत्री को इन मामलों का संज्ञान लेकर दलितों एवं आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। शेरगढ़ में हुई एक घटना की खबर साझा करते हुए गहलोत ने कहा, राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जाती थी एवं पुलिस हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ मजबूती से खड़ी दिखती थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद से ही प्रदेश में अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों एवं आदिवासियों के विरुद्ध अपराधों में दिसंबर 2023 की तुलना में 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में क्रमश: 32.7 फीसदी, 33.7 प्रतिशत, 34.1 फीसदी, 19.5 प्रतिशत, 62.5 फीसदी एवं 53.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने दावा किया, पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन आरोपी पीड़ितों पर आसानी से हमले कर पा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार के 'माथे पर कलंक' हैं जिनकी जिम्मेदारी से 'वह बच नहीं सकती है।'

विकास के लिए सामाजिक एकता जरूरी : पवार

» बोले- महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका चिंता की बात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी अशांति की आशंका पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि देश के विकास के लिए सामाजिक एकता जरूरी है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह ऐसा क्यों सोचते हैं। सामाजिक एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने मणिपुर में जातीय संघर्ष से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की भी आलोचना की। मणिपुर में पिछले साल मई में शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 200 से अधिक लोग मारे गए हैं।

पवार ने कहा, ''हमारे देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामाजिक एकता आवश्यक है। तनाव और विभाजन की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। देश में बढ़ते मतभेद के लिए जाति, धर्म और से परे एकता की आवश्यकता है।

प्रभावी कदम उठाने में विफल रही केंद्र सरकार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि दुर्भाग्यवश सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। मणिपुर में पिछले साल मई से ही बहुसंख्यक मेइती समुदाय और कुकी आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अभी तक हिंसा से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य का दौरा नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट रूप से प्रयासों की कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाऐ गये है। उन्होने कहा कि सामाजिक एकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सरकार की है।

अजित पवार समेत 41 विधायकों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट को दूसरे गुट के नेता जयंत पाटिल की याचिका पर नोटिस भेजा, जिसमें दलबदल और सेना-बीजेपी सरकार में शामिल होने के लिए अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत की यह प्रतिक्रिया इसके बाद आई है। शरद पवार गुट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत अजीत समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार और उनके साथ गए 41 विधायकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत इसी दिन शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करेगी।

मनु-सरबजोत ने साधा ऐतिहासिक निशाना

» चौथे दिन भारत की झोली में आया दूसरा पदक

» एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनीं मनु

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पेरिस। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन भारत ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीत लिया। मनु एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

इससे पहले इन दोनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि इससे पहले तीसरा दिन भारत के लिए खाली हाथ रहा। टेनिस में रोहन बोपन्ना हार कर बाहर हो गए। इसी के साथ टेनिस को अलविदा भी कहा दिया। निशानेबाजों, तीरंदाजों ने भी भी निराश किया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन जीत गए हैं। वहीं हॉकी टीम ने अर्जेंटीना से मैच ड्रा करवाकर अपनी हार बचा ली। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रान्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा और भारत को पदक और सरबोजत सिंह ने 580 अंक के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जुन बाबुता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में हार गए।

हॉकी में भारत और अर्जेंटीना मैच ड्रॉ

भारत और अर्जेंटीना के बीच हॉकी का मुकाबला खेला गया। जहां फुल टाइम के बाद दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर रहा। भारत ने 58वें मिनट में गोलकर स्कोर बराबर किया। आखिरी मिनट में भारत को एक मौका मिला, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने उसे सफल नहीं होने दिया। हॉकी के इतिहास में भारत ने अर्जेंटीना से दूसरी बार ड्रॉ खेला है। इससे पहले उसने 2004 में अर्जेंटीना से ड्रॉ खेला था।

लक्ष्य सेन की बेहतरीन जीत

ओलंपिक 2024 में डेब्यू कर रहे भारत के स्टार खिराड़ी लक्ष्य सेन ने धीमी शुरुआत से उबरकर सोमवार को पेरिस ओलंपिक की मेंस सिंगल बैडमिंटन के ग्रुप मैच में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को हरा दिया। सेन ने पहले मैच को 21-19 से जीता। वहीं दूसरे में उन्होंने 21-14 से जीत हासिल की थी।

महिला अपराध व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सपा ने योगी सरकार को घेरा

» विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार

» सीएम व नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक, माता प्रसाद ने उठाया मुद्दा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। मंगलवार को प्रदेश में महिला और बच्चों की सुरक्षा पर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि उस पर सीएम योगी ने कहा उनकी सरकार जब ऐंटी रोमियो स्क्वॉड लेकर आई थी, तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। हालत यह है कि महिला अपराधों से जुड़े ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी के लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर शामिल हैं।

उन्होंने तंज भी कसा। महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी खुद गंभीर खतरा हैं, अखिलेश और अपनी सरकार के आकंड़े गिनाते हुए कहा कि स्थिति अब कई गुना बेहतर है, सदन में समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने मुद्दा उठाया था।

सरकार ने ठोस कदम उठाए : सीएम योगी

महिला और बाल सुरक्षा और यौन शोषण से मुद्दे केवल बाहर से ही नहीं होते हैं। घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, इन दोनों को मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। महिला संबंध अपराध को जिसमें घरेलू हिंसा से लेकर यौन हिंसा की तुलना करूं, तो 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना 23-24 के बीच में साढ़े 17 प्रतिशत की कमी आई है। बलात्कार की घटनाओं में 25.30 प्रतिशत की कमी आई है। 17 से 2024 के बीच में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार ने अपनी प्रॉसिक्यूशन विंग को मजबूत किया है। 24 हजार 402 मामलों में भी तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से 24 के बीच में पास्को के तहत 9875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। महिलाओं के खिलाफ पास्को अधिनयम 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के खिलाफ पास्को के तहत 16718 को सजा हुई है। इसमें 21 को मृत्युदंड हुई है।

फोटो: सुमित कुमार

भाजपा के गच्चा देने से सपा आगे चली गई : शिवपाल

सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय की ओर संकेत करते हुए कहा कि चाचा को फिर गच्चा दे दिया गया। उन्होंने अखिलेश यादव के उस फैसले पर तंज कसा जिसमें सिद्धार्थनगर स्थित इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। इसके जवाब में शिवपाल ने कहा कि देखिए हमको गच्चा नहीं मिला है, पांडेय जी बहुत सीनियर हैं। हम लोग समाजवादी हैं, आपकी (स्पीकर सतीश महाना) तरफ से भी हमने कहीं न कहीं कुर्सी की तरफ इशारा किया था। मेरी कुर्सियां बदलती रहीं। मैं कहना चाहता हूं तीन वर्ष मैं आपके संपर्क में रहा तो गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल का इतना कहना था कि पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। उन्होंने कहा कि जब आपने गच्चा दिया तो आप पीछे चले गए और सपा आगे चली गई। अब देख लेना 2027 में सपा फिर से आगे आएगी और आपके जो डिप्टी सीएम हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे. 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं की आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर से गच्चा देंगे।

हमारी आवाज दबाई जा रही है: रागिनी

यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक रागिनी सोनकर महिला और बाल अपराधों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश। समाजवादी पार्टी विधायक ने योगी सवाल किया कि यूपी में आए दिन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता ज रहा है। उन्होंने कहा कि जवाब में सीएम ने खुद इस बात को माना है, आप खुद इस बात को मानते हैं कि बच्चों और महिलाओं के उत्पीड़न में यूपी टॉप पर हैं, सवाल उठाने पर हमें कहा जाता है कि आपने क्या किया। तब लोग इस पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज आवाज दबाई जा रही है। 2017 से 2023 तक महिलाओं के यौन शोषण और बच्चों पर अत्याचार के कितने केस दर्ज किए गए और सरकार ने उनकी मदद के लिए क्या काम किया।

फोटो :4 पीएम

धरना दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के विरोध में स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी के लविवि पर एनएसयूआई के छात्रों ने किया प्रदर्शन।

वायनाड भूस्खलन पर संसद में चर्चा

» बीजेपी अध्यक्ष नड्डा व नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मुद्दा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसदों ने वायनाड भूस्खलन पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा की मांग की है। इससे पहले सोमवार को संसद के दोनों सदनों में केन्द्रीय बजट पर चर्चा हुई थी।

वहीं आज की कार्रवाई में केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में 60 लोगों की मौत के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है।

सरकार की प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना : नड्डा

केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में 60 लोगों की मौत के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है।

भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की मैपिंग हो : राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने और पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इनसे निपटने के लिए कार्य योजना बनाए जाने की आवश्कता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। वह कल वायनाड का दौरा कर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव: वोटों की गिनती में हुआ गड़बड़झाला!

» 538 सीटों पर एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर

» विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर का दावा किया गया है। यह दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने किया है। इस रिपोर्ट के बाद सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी काई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सपा नेता व अयोध्या के सांसद ने कहा है कि अगर ठीक से गिनती की गई होती तो इंडिया गठबंधन की सीटें और ज्यादा आतीं।

उधर एडीआर के संस्थापक प्रो. जगदीप छोकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि 362 सीटों पर डाले गए कुल

मतों से 5 लाख 54 हजार 598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं, उन्होंने आगे कहा कि 176 सीटों पर डाले गए कुल 35 हजार 93 वोट अधिक गिने गए हैं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक,साल 2019 के आम चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों और गिने गए वोटों की संख्या में काफी अंतर है। प्रो. जगदीप छोकर ने लोकसभा चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस चुनाव में मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी करने में अत्याधिक देरी और मतदान केंद्रों के अलग-अलग आंकड़ों का अभाव और अंतिम मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर चुनाव परिणाम जारी किए गए या नहीं? ये सभी सवाल देश की जनता के मन में उठ रहे हैं।

सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा आयोग

एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग के आखिरी डेटा को अब तक जारी नहीं किया है। वहीं, आयोग अब तक डाले गए वोट और गिने हुए वोट में अंतर पर जवाब देने में असमर्थ है। मत प्रतिशत में वृद्धि कैसे हुई है। इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के परिणामों में 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए मतों में काफी विसंगतियां सामने आईं, अमरेली, अतिंगल, लथद्वीप और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को छोड़कर।

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट सत्यापन फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का उनके संबंधित वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग को खारिज करने वाले अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुनाया कि अदालत के 26 अप्रैल के फैसले की समीक्षा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है, जिसने वीवीपीएटी पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के पूर्ण सत्यापन की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। अपने संक्षिप्त आदेश में, पीठ ने कहा, हमने समीक्षा याचिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और 26 अप्रैल, 2023 के फैसले की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं पाया है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।